उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2024 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित डा० मान सिंह यादव, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-15 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
15-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में पिछले वर्ष खनिकर्म विभाग से सरकार को कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है?	जी हॉ। वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग का लक्ष्य रू0 5000.00 करोड़ था, जिसके सापेक्ष रू0 3987.31 करोड़ की प्राप्ति की गई, जो 79.74 प्रतिशत है।
(ख) खनिकर्म कार्य से राजस्व बढ़ाये जाने के संबंध में क्या सरकार की कोई कार्य योजना है?	जी हॉ।
(ग) यदि हॉ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	(1) अवैध खनन/परिवहन को रोकने के लिये वी0टी0एस0 प्रणाली को लागू किया जाना। (2) सम्भावित खनिज संसाधन (पोटेन्शियल मिनिरल रिसोर्स) एवं अवैध खनन को चिन्हित किये जाने हेतु निदेशालय स्तर पर भी खनन क्षेत्रों के सर्वे के लिये रिमोट सेन्सिंग लैब को स्थापित किया जाना। (3) संचालित खनन पट्टों की 24×7 निगरानी के लिये खनन क्षेत्रों पर लगे पी टी जेड कैमरा/वेब्रिज का लाइव फीड निदेशालय स्थित पी0एम0यू0/कमाण्ड सेन्टर पर प्राप्त किया जाना। (4) अवैध खनन/परिवहन को रोकने के लिये तथा खनन क्षेत्रों के सर्वे के लिये ड्रोन का उपयोग किया जाना। (5) मुख्य खनिज के खनन पट्टों के अनुश्रवण हेतु डैश बोर्ड तैयार किया जाना। (6) राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारियों एवं क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारियों के भी दायित्व निर्धारित किया जाना।

(7) अन्य राज्यों से होने वाले अवैध परिवहन को रोकने के लिये राजस्थान आदि प्रदेशों से ई-एम0 एम0 11/आई0एस0टी0पी0 पोर्टल को ए0पी0आई0 के माध्यम से जोड़ा जाना। वर्तमान में हरियाणा, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश राज्य के पोर्टल को विभागीय पोर्टल से ए0पी0आई0 के माध्यम से जोड़ा गया है।

(8) डी0एस0आर0 टू डीड साफ्टवेयर माड्यूल से एलर्ट भेजा जाना, ताकि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-60 आदि का कड़ाई से अनुपालन/अनुश्रवण हो सके।

(9) कार्यदायी संस्थाओं के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्यों में उपयोग किये गये खनिजों के सापेक्ष शत प्रतिशत रॉयल्टी जमा कराया जाना।

(10) मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान व उत्तराखण्ड आदि राज्यों में अपनायी जा रही नयी/भिन्न प्रैक्टिसेस में से, उ0प्र0 राज्य में लागू की जा सकने वाली प्रैक्टिसेस को लागू किया जाना।

(11) वित्तीय वर्ष 2024-25 का मदवार लक्ष्य निर्धारित करने के साथ-साथ भौतिक रूप से भी विभिन्न कार्यमदों के लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

(घ) यदि नहीं, तो क्यों?

प्रश्न नहीं उठता।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।